



लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

“असहमति एक लोकतांत्रिक अभव्यक्ति है कंतु इसे निश्चित मानदंडों के भीतर रहते हुए अभव्यक्त कया जाना चाहिए“ :

लोक सभा अध्यक्ष

...

प्रत्येक सांसद और वधायक राष्ट्र के आदर्शों,आशाओं और वश्वास का अभरक्षक है: लोक सभा अध्यक्ष

...

उत्तरप्रदेश वधान सभा ने संसदीय व्यवस्था की महान परम्परा को अक्षुण्ण रखा है जिससे नए बेंचमार्क स्थापित हुए हैं:

राज्यपाल,मध्यप्रदेश

....

“व्यवधानों से न केवल लोकतान्त्रिक संस्थाओं के कार्यकरण की निर्धारित प्रक्रिया अवरूद्ध होती है बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना के प्रति लोगों की आस्था भी क्षीण होती है“: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री

कैंप लखनऊ, 16 जनवरी 2020 : लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज उत्तर प्रदेश वधान सभा कक्ष, लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा क गत सात दशकों के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हमारी संसद की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की उत्तरोत्तर बढ़ती भागीदारी इस बात का सशक्त प्रमाण है क लोगों की लोकतंत्र के प्रति आस्था और वश्वास बढ़ा है और जितना लोकतंत्र के प्रति लोगों का वश्वास बढ़ा है, उतनी ही जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

श्री बिरला ने कहा क प्रत्येक सांसद और वधायक राष्ट्र के आदर्शों, आशाओं और वश्वास का अभरक्षक है और गरीब तबकों की आवाज उठाने में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा क संसदीय वाद-ववाद में जीवंतता और सक्रयता का संचार होता है और इसी लए ज्ञानपूर्ण वाद-ववाद के लए बोलने की स्वतंत्रता आवश्यकता है। यह वचार व्यक्त करते हुए क असहमति एक लोकतांत्रिक अभव्यक्ति है, उन्होंने कहा क इसे निश्चित मानदंडों के भीतर रहते हुए अभव्यक्त कया जाना चाहिए और संसदीय वाद ववाद निर्धारित नियमों के आधीन होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया क कसी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिध सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है क्यों क जनप्रतिनिध निरंतर जनता के साथ अंतर-संवाद करता रहता है। अतः वधायकों का यह कर्तव्य बनता है क कसी भी नीति के निर्माण के समय उनका पक्ष मजबूती से सदन में रखे और आम नागरिकों के सरोकारों के अनुरूप सरकार की नीतियों को प्रभावित करे।

सम्मेलन के पहले वषय 'बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में वधायकों का क्षमता निर्माण' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा क बजट सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति उपकरण है और बजट पर संसद और वधान सभाओं में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं हो सके, इसके लए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दे कर कहा क संसदीय और वधान मंडलों की समितियां सरकार के बजट, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं एवं उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती हैं और इनके सदस्यगण व भन्नु मुद्दों पर अपनी दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर कीमती सुझाव समिति को देते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की क संसदीय समितियां सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने के अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी

बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इस लए बजट पर संसद और वधान सभाओं में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं सुनिश्चित करने के लए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। दूसरे वषय अर्थात " वधायी कार्यों की ओर वधायकों का ध्यान केंद्रित करना' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा क सदस्यों को नियमों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान और संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त समझ होनी चाहिए ।

दिसंबर 2020 में देहरादून में संपन्न हुई भारत के वधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में पारित संकल्पों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा क सम्मेलन में संसद और वधान मंडलों की भूमिका को और वस्तुतः और प्रभावी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को और सशक्त करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित कए गए थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने अपने भाषण में कहा क उत्तर प्रदेश वधान सभा कई ऐतिहासिक चर्चाओं की गवाह रही है और यहाँ से उभरे कई सम्मानित सांसदों ने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को ग्रहण कया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश वधान सभा की सराहना की क उसने संसदीय व्यवस्था की महान परम्परा को अक्षुण्ण रखा है जिससे इस क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा क पीठासीन अधिकारियों के दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें न केवल सरकार और वपक्ष के सदस्यों को चर्चा में समुचित योगदान के लए अवसर देना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है क सदन का कार्य समुचित रूप तथा गरिमामयी संसदीय भाषा में चले।

इस अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क भारत ने हमेशा राष्ट्रमंडल के लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों और सद्घातों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना भी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भावना के अनुरूप है जिसमें देश की एकता और अखण्डता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता, भाईचारा, समानता और न्याय समाहित है। उन्होंने कहा क भारत पूरे राष्ट्रमंडल में लोकतंत्र और वकास का समर्थन करने और उसे बनाये रखने के लए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभी प्रयासों की सराहना करता है। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा क अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। यहाँ खान-पान, रहन-सहन, जाति, मत-पंथ, भाषा सहित अनेक क्षेत्रों में व भन्नता पाई जाती है। उन्होंने कहा क ऐसे में 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश में सभी को एक साथ लेकर चलना चुनौतियों से भरा है परन्तु हमारे देश ने सर्वसम्मति से तालमेल स्थापित करके अपने अनेकता और ववधता को अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में बड़ी सफलतापूर्वक समायोजित कर लया है और वश्व में शांति और सौहार्द का संदेश दिया है।

उन्होंने आगे कहा क राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभी देश भी एक परिवार के रूप में हैं और हमारा लक्ष्य लोकः समस्ताः सुखनो भवन्तु होना चाहिए अर्थात सम्पूर्ण मानवता सुख-समृद्ध और शाश्वत आनन्द प्राप्त करे। उन्होंने वचार व्यक्त कया क हमारी संसद तथा राज्य वधान मण्डल लोकतंत्र के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लए यह महत्वपूर्ण है क हम इन प्रतिनिधिक संस्थाओं की गरिमा और शुचिता को अक्षुण्ण बनाए रखें। उन्होंने कहा क अनेक अवसरों पर सदन की कार्यवाही व्यवधानों से बाधित होती है और सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इन व्यवधानों से सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इन व्यवधानों से न केवल इस संस्थाओं के कार्यकरण की निर्धारित प्रक्रिया अवरूद्ध होती है बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना के प्रति लोगों की आस्था भी क्षीण होती है। अतः जनप्रतिनिध होने के नाते हमारी प्राथमिकता सदन में जनता के वश्वास को बनाये रखना और उसे निरन्तर सुदृढ़ करना है तथा संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परम्पराओं को स्थापित करना है।

उत्तर प्रदेश वधान सभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने अपने स्वागत भाषण में कहा क राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय प्राचीन संसदीय दर्शन के पूर्णतः अनुरूप है। भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक मूल्य तथा संस्थायें सृष्टि रही है। यहाँ की परम्पराओं ने लोकतांत्रिक आदर्शों एवं प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा बनाये रखी है। सभा और समिति यहाँ ऋग्वैदिक काल से ही वद्यमान है। इस लए लोकतंत्र भारत की प्रकृति और प्रवृत्त है। उन्होंने कहा क लोकतंत्र का स्वरूप लगातार वस्तुतः हो रहा है और भारत जैसे वकासशील देशों में नवीन संसदीय परम्पराओं का निरन्तर वकास हो रहा है। वधायी संस्थाएँ अपनी परम्परागत भूमिकाओं के अतिरिक्त अन्य व भन्न क्षेत्रों में भी क्रियाशील हो रही हैं और ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी व्यापक और बहुमुखी होना स्वाभाविक है। उन्होंने आशा व्यक्त की क उत्तर प्रदेश में आयोजित यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश वधान सभा, श्री राम गो वन्द चौधरी ने अपने भाषण में कहा क संसदीय प्रणाली में वपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन में यदि वपक्ष न हो तो सत्ता पक्ष के स्वेच्छाचारी होने की संभावना बनी रहती है। वपक्ष सदन में प्रश्न पूछकर, व भन्न नियमों में प्रस्ताव लाकर, बजट में कटौती प्रस्ताव लाकर सत्ता पक्ष को चौकन्ना रखता है और जनहित के कार्यों के लए सचेष्ट करता रहता है। उन्होंने वचार व्यक्त कया क वपक्ष नागरिकों के अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक होता है। उन्होंने जोर देकर कहा क स्वस्थ संसदीय प्रणाली के लए आवश्यक है क सदन में प्रत्येक जनप्रतिनिध को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

अपने धन्यवाद उद्बोधन में माननीय सभापति, उत्तर प्रदेश वधान परिषद श्री रमेश यादव ने कहा क राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का एक दीर्घ इतिहास रहा है। सौ वर्षों से भी अधिक समय से यह संघ अपनी महत्वपूर्ण सेवायें दे रहा है। राष्ट्रमंडल के सम्मेलनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी देशों की वधायी संस्थाएँ और अधिक सृष्ट हुई हैं।

इस अवसर पर, श्री बिरला ने उत्तर प्रदेश वधान सभा द्वारा प्रकाशत एक स्मारिका का वमोचन भी कया।

इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने वधान सभा फोरम में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कया । इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश वधान सभा के वकास की यात्रा को उकेरा गया है।

मध्याह्न में, सम्मेलन के पहले वषय "बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में वधायकों का क्षमता निर्माण" पर चर्चा आरम्भ हुई। की नोट भाषण देते हुए राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा क भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की आकांक्षा हर लोक प्रतिनिध के हृदय में है। इसके लए यह आवश्यक है क बजट को समझने और उसकी समीक्षा करने के लए उनके पास आवश्यक कौशल और तकनीकी जानकारी हो। उन्होंने कहा क यह वध निर्माताओं का दायित्व है क वे तकनीकी शब्दावली को समझे और सामाजिक आर्थिक संकेतकों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करें। इस सन्दर्भ में उन्होंने तकनीकी वशेषज्ञों की भूमिका पर बल दिया जिससे वतीय नियमों, नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिवेदनों और बजट से सम्बन्धित अन्य तकनीकी आयामों से सदस्यों को अवगत कराया जा सके। कई माननीय पीठासीन अधिकारियों ने इस वषय पर अपने वचार रखे।

“DISSENT IS A DEMOCRATIC EXPRESSION BUT IT SHOULD BE ARTICULATED WITHIN PRESCRIBED NORMS”: LOK SABHA SPEAKER

...

“EVERY MEMBER MP AND MLA IS CUSTODIAN OF IDEALS, ASPIRATIONS AND TRUST OF THE NATION”: LOK SABHA SPEAKER

...

“UTTAR PRADESH VIDHAN SABHA IS UPHOLDER OF HIGH PARLIAMENTARY TRADITIONS AND PRACTICES”: GOVERNOR, MADHYA PRADESH

...

“DISRUPTIONS NOT ONLY OBSTRUCT THE WORK BEING CARRIES OUT IN THOSE ORGANIZATIONS BUT MAKE PEOPLE LOSE THEIR FAITH IN THE FUNDAMENTAL SPIRIT OF DEMOCRACY”, CHIEF MINISTER, UTTAR PRADESH

Camp Lucknow, 16 January 2020: Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla inaugurated the 7th CPA India Region Conference at the Uttar Pradesh Vidhan Sabha today. Speaking on the occasion, Shri Birla said that in the past seven decades, Parliament has done commendable work to usher in social, economic and political changes. He observed that the unflinching belief of people in our democracy is our strength and over the years, their increasing participation in our electoral process is testimony to this fact. Further, with the rising aspirations of the people, the responsibility of representatives towards their representatives had also increased, he added.

Shri Birla said that every Member of Parliament and MLA is custodian of ideals, aspirations and trust of the nation and voices the grievances of the poor. He asserted that Parliamentary discourse resonated vibrancy and dynamism of our democracy and norms of freedom of expression should imbibe informed and uninterrupted discussions. Thus parliamentary discussions should concur to established rules and norms. He further said that elected representatives serve as a link between the people and the Government because they are in constant touch with the people. It is, therefore, the responsibility of the elected representatives to vociferously put forth the views of their constituents when legislations are discussed in the House and also to ensure their demands are accommodated in the policies and programmes pursued by the Government.

Speaking on the theme for the first Plenary, 'Capacity Building of Legislators for scrutinizing Budgetary Proposals', Lok Sabha Speaker said that Budget is a key instrument of Government's financial policy, and to have informed and meaningful discussions on the Budget, capacity building of legislators is crucial. The role of parliamentary committees, in this respect, is also important because committees evaluate and monitor Government budget, policies and programmes and also provide a platform to legislators to give their valuable opinion, irrespective of party or political considerations. He expressed satisfaction that parliamentary committees have been working to ensure good governance by bringing transparency and answerability in Government functioning. Capacity building of legislators, is also necessary to ensure proactive and meaningful discussions on the budget. Further, speaking on the theme for the second Plenary, 'Enhancing Focus of Legislators on Legislative Business', Shri Birla said that legislators should have profound understanding of rules and procedures and also our Constitutional provisions.

Referring to the Resolution passed during the 79th Conference of Speakers and Presiding Officers of Legislative Bodies in India, Lok Sabha Speaker highlighted that the Conference has passed a few Resolutions, to comprehensively streamline the working of our Parliament and legislatures and to ensure effective participation of legislators.

The Governor, Madhya Pradesh Shri Lal ji Tandon recalled that he had witnessed in the august Chamber of Uttar Pradesh Vidhan Sabha many historical debates by eminent Parliamentarians who later occupied high constitutional offices. He complimented the Uttar Pradesh Vidhan Sabha for upholding high parliamentary traditions and practices and thereby setting new benchmarks. Shri Tandon said that the Presiding Officers' responsibilities are very challenging as they have to not only respect the mandate of the House by giving opportunities to members belonging to both the Treasury and the Opposition benches, but also to ensure that the proceedings of the House are conducted in a smooth manner and in a dignified language.

Speaking on the occasion, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath said that India has always shown commitment towards the democratic values, ideals and the tenets of the Commonwealth because the fundamental principles of Indian democracy resonate with the spirit of Commonwealth Parliamentary Association. He observed that the unity, integrity of the nation, its independence, secularism, fraternity, equality and justice are inherent in Indian ethos. He also emphasized that unity in diversity is the hallmark of India which manifests in food, ways of living, castes, creeds, religions, languages and various other fields. Hence bringing about a harmony among the 130 crore people in this country is a daunting task but our nation has unanimously established a balance and successfully merged its differences and diversities in our democratic system transmitting a message of peace and goodwill to the world, he added.

Shri Yogi Adityanath also observed that since all the nations constituting the Commonwealth Parliamentary Association are in the form of a family, our goal should be implying that the entire humanity should attain happiness, prosperity and eternal joy. He further underlined that Parliament and the State Legislatures act as the nucleus of democracy. Thus, it is important to sustain the dignity and uprightness of these representative associations for strengthening democracy. He noted that the proceedings in the Legislatures often get impeded by numerous hurdles on various occasions resulting in a dissipation of precious time. These hurdles not only obstruct the work being carried out in those organizations but make people lose their faith in the fundamental spirit of democracy. Hence, the priority as the representative of the masses is to sustain the faith of the people in the Parliament as well as Legislature to establish the lofty traditions of parliamentary democracy, Shri Yogi Adityanath said.

Welcoming the Delegates Hon'ble Speaker, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Hriday Narayan Dikshit said CPA is entirely concordant with the ancient parliamentary philosophy of India. Our traditions have sustained faith in democratic ideals and representative organizations. The Sabhas and Samitis have existed since Rigvedic times and democracy is, thus, inherent in character of India. He said that the form of democracy is continuously expanding in developing countries like India. As Legislative bodies besides performing their traditional roles are making a foray into newer fields, it is natural that elected representatives should also have an extensive and multifaceted role.

Delivering the Vote of Thanks, Chairman, Uttar Pradesh Vidhan Parishad, Shri Ramesh Yadav said that the Commonwealth Parliamentary Association Union has been rendering its important services for more than 100 years and Legislative institutions of all countries have improved further through Commonwealth conferences and programmes.

The Leader of Opposition, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Ram Govind Chaudhary, said that the Opposition plays keeps the Government in check by asking questions, cut motions in budget and through motions under relevant rules. He emphasized that it is important for the healthy parliamentary system that each member rises above party considerations.

On the occasion, Shri Birla also released a souvenir, brought out by Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to commemorate the event.

Earlier, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla inaugurated an exhibition titled "Uttar Pradesh Vidhan Sabha: Historical Background", depicting the journey of evolution of U.P. Legislative since 1922. The exhibition has been set up in the foyer of the Uttar Pradesh Vidhan Bhawan.

Later, the Conference took up discussions on the first plenary 'Capacity Building of Legislators for scrutinizing Budgetary Proposals'. Delivering the keynote address, Deputy Chairman, Rajya Sabha Shri Harivansh observed that it is the common aspirations of all representatives to make India an economic superpower. For this, it is necessary that lawmakers have adequate skills and knowhow to scrutinize the budget. He emphasized that it is incumbent upon lawmakers to understand technical terminology and techniques to decipher social and economic indicators. In this regard, he highlighted the role of technical experts in explaining about the financial rules, C&AG reports and other technical aspects of the budget. Many Presiding officers shared their views on the subject.